

कार्बन मुक्त वदियुत उत्पादन के प्रति G7 की प्रतिबद्धता

प्रलिस के लिये:

G7 शखर सम्मेलन हरिशामि, वैश्विक ऊरजा संकट, शुद्ध-शून्य गरीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, IPCC, प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना, हरति ऊरजा गलियारा, राष्ट्रीय समारट गरडि मशिन (NSGM)

मेन्स के लिये:

G7, कार्बन-मुक्त वदियुत उत्पादन से संबंधति भारतीय पहल ।

चरचा में क्यों?

सात देशों के समूह (Group of Seven- G7) के जलवायु और ऊरजा मंत्रियों तथा दूतों ने वर्ष 2035 तक कार्बन मुक्त वदियुत उत्पादन सुनिश्चित करने एवं कोयले की चरणबद्ध समाप्ता/फेज-आउट की दशि में तेज़ी लाने हेतु प्रतिबद्धता जताई है । मई 2023 में हरिशामि में आयोजति G7 शखर सम्मेलन से पहले यह समझौता सापपोरो, जापान में कथि गया था ।

- G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भारत को शखर सम्मेलन में 'अतिथि' के रूप में भी आमंत्रति कथि गया था ।

प्रमुख बडि

- मौजूदा वैश्विक ऊरजा संकट और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए इस समझौते में वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य गरीनहाउस गैस (Greenhouse Gas- GHG) उत्सर्जन हेतु स्वच्छ ऊरजा को अपनाने में तेज़ी लाने का आह्वान कथि गया है ।
 - G7 देशों ने वर्ष 2030 तक GHG उत्सर्जन को लगभग 43% और वर्ष 2035 तक 60% कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दथि ।
- IPCC की AR6 रिपोरट के अनुसार, जसिमें शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता को इंगति कथि गया है, प्रतिभागी देशों ने अपतटीय प्लेटफॉर्मों से 1,000 गीगावाट सौर ऊरजा और 150 गीगावाट पवन ऊरजा का उत्पादन करने के लिये सौर एवं पवन ऊरजा क्षेत्र में निवेश में तेज़ी लाने पर सहमति वियकत की ।
- इसमें पुष्टि की गई है कि जीवाश्म ईंधन सबसडि पेरसि समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत है और वे वर्ष 2025 तक अकुशल जीवाश्म ईंधन सबसडि को खतम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ।
- वे प्रमुख मुद्दे जनि पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई:
 - अन्य देशों को उनके ऊरजा संक्रमण और ऊरजा दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिये और अधिक सहायता दथि जाने के संबंध में ।
 - UNFCCC COP 27 में प्रतिवर्ष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई गई थी, परंतु वकिसति देशों द्वारा कथि जाने वाले वत्तीय योगदान में कमी आई है ।
 - ब्रटिन और कनाडा द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव ।

G7:

- परिचय:
 - सात देशों का समूह (G7) एक अंतर-सरकारी संगठन है जसिमें सात प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं ।
 - G7, मूल रूप से G8 (जब इसमें शामिल होने के लिये रूस को आमंत्रति नहीं कथि गया था), को वर्ष 1975 में विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्ताओं के एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापति कथि गया था ।
- उद्देश्य:
 - G7 का प्राथमिक उद्देश्य इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है ।
 - यह व्यापार, आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहति पारस्परिक चत्तीय मुद्दों पर चरचा करने के लिये एक मंच के रूप में

कार्य करता है।

● **जलवायु परिवर्तन, गरीबी में कमी लाना** और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है।

■ **बैठकें:**

● G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है जिसमें सदस्य देश वभिन्न मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिये एकत्रित होते हैं।

● इस शिखर सम्मेलन का आयोजन क्रमिक रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।

■ **महत्त्व:**

● **आर्थिक शक्तियाँ:** G7 देश विश्व की कुछ सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो दुनिया की 40 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

● ये वैश्विक व्यापार नीतियों और वनियमों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव के साथ विश्व के अग्रणी व्यापारिक राष्ट्रों में भी शामिल हैं।

● **वैश्विक शासन:** G7 वैश्विक शासन की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसका **संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन** जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।

● इसकी नीतियों और नरिणियों का वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

■ **आलोचनाएँ:**

● G7, जिसमें विश्व की कुछ सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-चौथाई हिस्से के लिये ज़िम्मेदार है।

● यह आश्चर्यचकित कर देने वाला आँकड़ा है जो जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम चलाने में इन देशों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

● G7 को विश्व की आबादी का वशिष्ट और अप्रतिनिधि होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह वैश्विक आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है एवं भारत तथा चीन जैसे देश इससे बाहर हैं, जो कि प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ हैं।

● आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है कि हाल के वर्षों में G7 के प्रभाव में कमी आई है क्योंकि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

कार्बन मुक्त वदियुत के संबंध में भारत की पहल:

■ **प्रधानमंत्री सहज वदियुत हर घर योजना (सौभाग्य):** विश्वसनीय और सस्ती बजिली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना।

■ **ग्रीन एनर्जी कॉरडोर (GEC):** भारत के राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ग्रडि से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा को सिक्रोनाइज़ करना।

■ **नेशनल स्मार्ट ग्रडि मशिन (NSGM) और स्मार्ट मीटर नेशनल परोग्राम (SMNP):** भारत के वदियुत क्षेत्र को सुरक्षित, अनुकूली, टिकाऊ व डिजिटल रूप से सक्षम आधुनिक पारस्थितिकी तंत्र बनाना।

■ **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT):** ऊर्जा प्रभावशीलता में सुधार करना और उन औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना जिन्हें वनियमित करना मुश्किल है।

■ **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (NDCs):** अद्यतन NDC के अनुसार, भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष **2030 तक** अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को **45% तक** कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग **50%** संतथी वदियुत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

UPSC यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि एक समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं?

अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड
ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वयितनाम
इंडोनेशिया, जापान, सगिपुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

??????????:

प्रश्न. "सतत, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये अनवार्य है।" इस संबंध में भारत में हुई प्रगतिपर टपिपणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. पारंपरिक ऊर्जा की समस्या को दूर करने के लिये भारत के हरति ऊर्जा गलियारे पर एक टपिपणी लखिये। (2013)

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/g7-s-commitment-towards-carbon-free-electricity-production>

